एस.एस. निज्जर और निर्मल यादव,जे.जे. के समक्ष

भारत संघ और अन्य लोग - *याचिकाकर्ता*

बनाम

सर्वेश कौशल – *उत्तरदाता*

*सी.डब्लू.पी. न.*15169 / कैट ऑफ 2002

29 जुलाई, 2005

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – सतर्कता मैनुअल, वॉल्यूम. I- अध्याय 3, पैराग्राफ 1.8, 3.10, 3.10(i), 3.11(ii) –ऐफ.सी.आई. के एक अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य की व्युत्पत्ति का आरोप –उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की शुरुआत – केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष यही मामला जांच के लिए लंबित है– पैरा 1.8 प्रदान करता है कि एक बार किसी मामले को सीबीआई ने जांच के लिए संदर्भित कर लिया तो उसकी आगे की जांच उनके पास छोड़ दी जानी चाहिए और विभाग द्वारा समानांतर जांच से बचा जाए– पैरा 3.18 प्रदान करता है कि लोक सेवक पर लागू नियम के तहत अनुशासनात्मक दीक्षा शुरू करने के लिए कोई कानूनी पट्टी नहीं है जहां अपराधी अभियोजन पहले से ही लंबित है – एक पूर्ण परीक्षण के बाद न कोई आपराधिक मुकदमा और न बरी होगा – सीबीआई प्रारंभिक संचालन जांच / जांच – विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई सीबीआई द्वारा जांच के पूरा होने पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर होगी – पैराग्राफ 3.10, 3.11 (i) और 3.11(ii) भी प्रदान करते हैं विभाग एक ही मामले में समानांतर या दोहरावदार पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है – याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस को स्पष्ट रूप से मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है- क्या न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र OA का मनोरंजन करने के लिए समर्थ है क्योंकि अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही सतर्कता मैनुअल प्रावधानों के विपरीत है -अभिनिर्धारित, हाँ-याचिका खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

अभिनिर्धारित, सतर्कता मैनुअल, वॉल्यूम के अध्याय 3 के पैरा 1.8. में, मैं स्पष्ट रूप से प्रदान करता हूं कि एक बार एक मामले को सीबीआई जांच के लिए संदर्भित किया गया है, आगे की जांच को उनपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक समानांतर जांच/ विभाग, संगठन से बचना चाहिए. विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही, सीबीआई द्वारा जांच के पूरा होने और रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए निर्देश सतर्कता मैनुअल के पूर्वोक्त धाराओं के अनुरूप हैं।

(पैरा6)

आगे अभिनिर्धारित, सीबीआई को सौंपा गया मामला, विभागीय रूप से मामले को फिर से खोलने का कोई औचित्य नहीं था। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को जारी किए गए शो कारण नोटिस को रद्द कर के कोई त्रुटि नहीं की है। हम यह स्वीकार नहीं करते कि सतर्कता मैनुअल में निहित निर्देश मान्य नहीं हैं। ट्रिब्यूनल ने सही तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि पैरा 1.8 के मद्देनजर विभाग शो जारी नहीं कर सकता था।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्धारित, मैनुअल के पैरा 3.18 का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं है। यह प्रदान करता है कि *लोक सेवक पर लागू नियम के तहत अनुशासनात्मक दीक्षा शुरू करने के लिए कोई कानूनी पट्टी नहीं है जहां अपराधी अभियोजन पहले से ही लंबित है।* वर्तमान मामला में, प्रतिवादी के खिलाफ लंबित किसी भी आपराधिक कार्यवाही का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई द्वारा केवल एक प्रारंभिक जांच संचालित की जाती है। आपराधिक कार्यवाही लंबित बताई जाती है जब कोई आरोप आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाया जाता है।पूर्वोक्त अवस्था जांच पूरी होने और रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद आती है, जब विचार किया जाता है कि क्या आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित, ट्रिब्यूनल के पास ओ.ए. का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां अधिकार क्षेत्र के बिना, शो कारण नोटिस को धैर्यपूर्वक दिखाया गया है। शो कारण नोटिस सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के कुल उल्लंघन में जारी किया गया था। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी को अंतिम राहत नहीं दी। विभाग के पास विभागीय कार्यवाही लेने के लिए स्वतंत्रता है, अगर सीबीआई द्वारा जांच का निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए उक्त सबूत नहीं है ।

(पैरा 15)

सतपाल जैन, सीनियर वकील विजय चौधरी के साथ, *याचिकाकर्ता* के लिए अधिवक्ता।

राजीव आत्मा राम, सीनियर अधिवक्ता एच एस सेठी प्रतिवादी के लिए,

निर्णय

एस.एस.निजजर,जे (ओरल)

(1) हमने पार्टियों के वकीलों को सुना लिया और कागज-पुस्तक का उपयोग किया।

(2) उतरदाता न.1 श्री सरवेश कौशल, आईएएस अधिकारी (इसके बाद "कौशल" के रूप में जाना जाता है) को मेमोरेंडम नं. C-123015/4/98-AVU, दिनांक 30 जून, 2000 (अनुबंध P-1) भेज गया और आरोप लगाया गया की 6 सितंबर, 1993 से 30 अप्रैल, 1998 के दौरान वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक,ऐफ.सी.आई.,पंजाब चंडीगढ़, में कार्य करते समय वह कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और भक्ति बनाए रखने में विफल रहा। यह आरोप लगाया गया था कि 4 अगस्त,1994 को प्रबंध निर्देशक, एफसीआई द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश, जिसमें धान के भंडारण की अनुमति पंजाब में मिलर्सके परिसर को दी थी,उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। निर्देशों को लागू न करके,उसने एफसीआई के हित को खतरे में डाल दिया। खतरनाक स्थिति और बड़े पैमाने पर पंजाब के जिले भटिंडा में धान के दुरुपयोग को देखते हुए, निवारक लेने की तत्काल आवश्यकता थी, जैसे कि एफसीआई द्वारा धान का भौतिक सत्यापन ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि समान विकृतियों पर अंकुश लग गया है। कौशल पर यह आरोप है की वह केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे थे, क्षेत्रीय कार्यालय से निर्देश जारी करना, बिना उनकी पालन का पता लगाए। इसलिए, यह आरोप लगाया जाता है कि वह पर्यवेक्षी नियंत्रण के अभ्यास में सावधानी और उचित देखभाल करने में विफल रहा है,और इसलिए, वह कर्तव्य के अपमान का दोषी है। मेमोरेंडम (अनुबंध **पी-1) में उठाए गए मुद्दों पर** अपनी स्थिति समझाने के लिए, ज्ञापन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर निर्देशित किया गया था। इसे कौशाल ने 11 जुलाई, 2000 को प्राप्त किया था। उन्होंने 16 जुलाई, 2000 को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सामने आवेदन प्रस्तुत किया,की से उठाए गए बिंदुओं के संबंध में आधिकारिक रिकॉर्ड का निरीक्षण की अनुमति मांगी, ताकि वह निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की स्थिति में हो। संबंधित मंत्रालय द्वारा जवाब नहीं दिया गया. उसने 26 जुलाई, 2000को अनुस्मारक प्रस्तुत किया। अंततः, उन्हें 28 अगस्त, 2000 को एक संचार प्राप्त हुआ। उन्हें सूचित किया गया था कि " आवेदक को इस स्तर पर आधिकारिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है "। उसे सूचित किया गया उसे सूचीबद्ध दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पूरा अवसर जांच के दौरान दिया जाएगा, यदि मामला स्थापित किया गया। उन्हें निर्देशित किया गया की वह

इस पत्र,जो 3 अगस्त, 2000 को उनके द्वारा प्राप्त किया गया था, उसकी प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दे। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्र जांच शुरू की थी, भले ही वही मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच / प्रारंभिक जांच लंबित था। इस कार्यवाही का कौशाल ने OA नं. 632-सीएच केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पंजाब, चंडीगढ़ के सामने (इसके बाद "के रूप में जाना जाता है ट्रिब्यूनल") विरोध किया था। सूचना जारी किए जाने पर, उत्तरदाता दिखाई दिए और एक लिखित बयान दर्ज किया। यह निवेदन किया गया था कि जारी ज्ञापन किया जाना केवल एक प्रारंभिक जांच / जानबूझकर औपचारिक चार्ज-शीट जारी करने से पहले किया गया था, केवल प्रतिक्रिया अधिकारी से पूछा गया था। यह भी कहा गया था कि इस स्तर पर अधिकारी को किसी भी दस्तावेज की आपूर्ति आवश्यक नहीं है। यह भी कहा गया था कि मूल अनुप्रयोग समय से पहले है। यह कहा गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट नेकई निर्णयों में कहा है जांच की प्रारंभिक चरण की कार्यवाही के खिलाफ अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 4 जुलाई, 2001 के अपने आदेश से, ट्रिब्यूनल ने मूल आवेदन का निपटान किया है अधिकारियों को सतर्कता नियमावली के पैरा 1.8 के प्रावधानों को और टिप्पणियों पर प्रकाश डाल कर विचार करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, यह निर्देशित किया गया है निर्णय लेने तक, ज्ञापन के बल पर आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुखी पूर्वोक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता की समीक्षा के लिए चले गए। समीक्षा आवेदन 23 मई, 2002 को दायर किया गया था। कौशाल की ओर से प्रारंभिक आपत्ति की गई थी कि समीक्षा आवेदन समय वर्जित है क्योंकि दाखिल करने में 282 दिनों की देरी थी वही, 30 दिनों के समय की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद मांगे गए आदेश की एक प्रति की प्राप्ति की तारीख से समीक्षा की। प्रारंभिक आपत्ति के समर्थन में, कौशाल के लिए पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर निर्भर थे, **के.अजीत बाबू** *बनाम* **भारत संघ (1).** यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई नए और महत्वपूर्ण की खोज नहीं हुई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की सूचना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में लेने के बाद याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की गई।

(1) (1997) (6) एस.सी. 473

(3) श्री सतपाल जैन, याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर वकील ने तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने है O.A के मनोरंजन में एक गंभीर त्रुटि की है। अपराधी अधिकारी के खिलाफ केवल एक प्रारंभिक जांच आयोजित की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान, ट्रिब्यूनल के पास पूरी जांच को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सीनियर वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल का निर्णय कानून के अच्छी तरह से बसे प्रस्तावों के विपरीत है *अर्थात.* (1) ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी अधिकारी के बरी होने के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और (2) ट्रिब्यूनल के पास शो-कारण नोटिस को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी उस अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने से पहले, जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीनियर वकील भी यह स्वीकार करता है कि ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से सतर्कता मैनुअल के अध्याय 3, वॉल्यूम पैराग्राफ 1.8 पर भरोसा किया है। प्रावधान प्रारंभिक विभागीय जांच के आयोजन पर पूर्ण बार नहीं लगाता। तथ्य यह है कि प्रावधान अनुच्छेद 3.18 में किया गया है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है। प्रस्तुतियाँ के समर्थन में, सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

(4) श्री राजीव आत्मा राम, उत्तरदाताओं के लिए पेश होने वाले सीनियर वकील ने समान मात्रा की वीभत्सता के साथ प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रयोज्यता के संबंध में सतर्कता मैनुअल के पैरा 3.18.पर कोई दलील नहीं दी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त प्रावधान को ट्रिब्यूनल द्वारा ध्यान में नहीं लिया गया इसलिए उसके आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है, जो पूरी तरह से निराधार है। वास्तव में, पूर्वोक्त दलील याचिकाकर्ता द्वारा समीक्षा याचिका में भी नहीं ली गई थी। यह केवल तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित सीनियर. वकील ने दीं सतर्कता मैनुअल के पैरा 3.18 के संबंध में प्रस्तुतियाँ की, उत्तरदाता के सीनियर. वकील ने कहा कि अन्यथा भी, सतर्कता मैनुअल के पैराग्राफ 3.18 को पैराग्राफ 3.10, 3.11 (i) और 3.11 (ii) के साथ पढ़ना होगा। उपरोक्त पैराग्राफ का अध्ययन करने से पता चलता है कि विभाग उसी मामले में समानांतर या दोहराव पूछताछ रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सीनियर वकील ने आगे प्रस्तुत करता है ट्रिब्यूनल ने सही निष्कर्ष निकाला है कि विभाग ने पहले भी उन्हीं आरोपों की जांच की थी। उसी जांच के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने कौशाल को विशेष रूप से यह कहते हुए लिखा था कि "कुछ मुद्दों से संबंधित जांच,

जैसे कि 1994-95 में एफसीआई धान के गैर-मिलिंग के दुरुपयोग तब से सक्षम अधिकारी के आदेश के साथ बंद कर दिया गया है," सीनियर वकील ने कहा कि अधिकारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और रिट याचिका खारिज करने की हकदार है।

(4 – A) हमने दोनों पक्षों के है सीनियर वकील द्वारा सबमिशन पर विचार किया। सीनियर के संबंधित प्रस्तुतियाँ पर विचार करने से पहले, सतर्कता मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों को यहां पुन: पेश किया जा रहा है : –

"1.8 एक बार एक मामले को सीबीआई जांच के लिए संदर्भित किया गया है, आगे की जांच को उनपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक समानांतर जांच/ विभाग, संगठन से बचना चाहिए. विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही, सीबीआई द्वारा जांच के पूरा होने और रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना चाहिए।

2.3 प्रारंभिक जांच के दौरान, जनता संबंधित नौकर को कहने का अवसर दिया जा सकता है कि वह उसके खिलाफ आरोपों के बारे में क्या कहना चाहता है ताकि उसे यह पता चले कि क्या वह कोई संतोषजनक जानकारी या स्पष्टीकरण देने की स्थिति में है। ऐसी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, संबंधित लोक सेवक के साथ अनुचित तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है। यह उचित है, इसलिए, जांच अधिकारी संदिग्ध अधिकारियों के "तथ्यों" प्राप्त करने की कोशिश करता है कि जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। इस स्तर पर उसे कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने का कोई सवाल ही नहीं है।

3.10 यदि जांच पूरी होने पर, सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूतआ रहे हैं, यदि अभियोजन को राष्ट्रपति के नाम पर मंजूरी की आवश्यकता है तो फिर अंतिम रिपोर्ट ऐसे मामलों की सतर्कता जांच केंद्रीय को भेज दी जाएगी। अन्य मामलों में, रिपोर्ट अभियोजन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकरण को भेज दी जाएगी। रिपोर्ट मंजूरी आदेश फार्म *(देख* अध्याय VII) के साथ, और खारिज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पदनाम और रैंक देगा, जो

सेवा और कानून या नियमों के तहत अपराधी अधिकारी को हटाने के लिए सक्षम है। अध्याय VII में रिपोर्टों पर आगे की कार्यवाही के बारे में वर्णित है।

3.10 (i) गंभीर प्रकृति के आरोप औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि जनता नौकर के खिलाफ नियमित विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अंतिम रिपोर्ट के साथ (ए) प्रभारी के मसौदा लेख में तैयार किया गया निर्धारित प्रपत्र *(देख* अध्याय X), (b) प्रत्येक शुल्क के समर्थन में प्रतिनियुक्ति का विवरण, और (ग) दस्तावेजों और गवाहों की सूची जिसपर आरोपों को साबित करने के लिए भरोसा किया है।

3.11 (ii) जबकि औचित्य अभियोजन या नियमित विभागीय कार्यवाही के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तब सरकारी सेवक की ईमानदारी या अखंडता के बारे में उचित संदेह होता है, ऐसी अंतिम रिपोर्ट अनुशासनात्मक अधिकार के नोटिस में अनियमितता या लापरवाही की प्रकृति का प्रशासनिक मामलों को लाती है, जिसे संभव या उचित माना जा सकता है। "

(5) पूर्वोक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चूंकि *एक बार किसी मामले को सीबीआई ने जांच के लिए संदर्भित कर लिया तो उसकी आगे की जांच उनके पास छोड़ दी जानी चाहिए और विभाग द्वारा समानांतर जांच से बचा जाना चाहिए।* यह भी देखा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय हमेशा किसी एडिटोनल सामग्री को सीबीआई के नोटिस में लाने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि मामला सीबीआई द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। ऐसी परिस्थितियों में, पैरा 2.3 लागू हो जाता। एक बार सीबीआई ने सतर्कता मैनुअल के पैरा 1.8 के मुताबिक इस मामले को बंद कर दिया,तब विभाग को प्रारंभिक जांच संचालन में अपने हाथ में लेगा। हम श्री एस.पी. जैन, सीनियर वकील की इस बात से असहमत हैं कि ट्रिब्यूनल ने ओ.ए. के मनोरंजन में एक गंभीर त्रुटि की है। हम सीनियर वकील की यह सबमिशन भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि ट्रिब्यूनल ने विभाग की आगे की जांच को बंद कर दिया। हमें सीनियर के इस सब्मिस्शन में कोई योग्यता नहीं मिलती जो कहता है कि ट्रिब्यूनल के पास शो-कारण नोटिस को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी उस अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने से पहले, जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। हम यह भी मानते हैं कि

श्री एस.पी. जैन द्वारा सतर्कता मैनुअल के पैरा 3.18 पर आधारित सुबमिससीऑनस अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वे इस प्रकार थे: –

"19. सुनवाई के दौरान यह विवादित नहीं था कि सीबीआई पहले ही मामले को जब्त कर चुकी है और उसने पंजीकरण कर लिया है उसी विषय पर प्रारंभिक जांच सीबीआई द्वारा आवेदक और जांच प्रगति पर है और सीबीआई द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि एक विशेष एजेंसी है। एक बार ऐसा होने पर, यह प्रशासनिक मंत्रालय से अपेक्षित था कि वह अतिरिक्त सामग्री या जानकारी सीबीआई के नोटिस में लाएंगे, जो सीबीआई को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाए और इस तरह के अतिरिक्त जानकारी या सामग्री पर गौर करे जो प्रशासनिक मंत्रालय ने उपलब्ध करवाई है। यदि मामला सीबीआई द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। ऐसी परिस्थितियों में, पैरा 2.3 लागू हो जाता। एक बार सीबीआई ने सतर्कता मैनुअल के पैरा 1.8 के मुताबिक इस मामले को बंद कर दिया,तब विभाग को प्रारंभिक जांच संचालन में अपने हाथ में लेगा। यह उस स्थिति में दोहरे खतरे की प्रकृति में होगा। हालाँकि, हमारे लिए यह प्रतीत होता है कि सतर्कता मैनुअल के 1.8 पैरा में किए गए प्रावधान पूर्ण और सार्वजनिक हित के लिए शामिल किया गए है, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानी न हो। उस संदर्भ में सतर्कता मैनुअल का पैरा 2.3 पढ़ने पर यह पैरा 1.8 में निहित प्रावधान के साथ संघर्ष नहीं करता। हालाँकि, यह अभी भी प्रशासनिक मंत्रालय के लिए खुला है कि वह अपने स्तर पर सामग्री एकत्र करें और एकत्रित सामग्री को सीबीआई को पास करें। इस मामले में, जैसा कि पहले ही देखा गया है, सीबीआई द्वारा पहले से ही मामले को जब्त कर लिया गया है और प्रशासनिक मंत्रालय को जांच के परिणाम का इंतजार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो कानून के अनुसार यदि अनुमेय हो तो बाद में, मामले के साथ संसाधित करें।

20. आरोपों के मलफाइड और वैधता या अन्यथा शो नोटिस में जाने के बिना और इस आरोप के संबंध में कि सीबीआई ने पहले ही मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच चल रही है और सक्षम प्राधिकारी ने जांच के बाद मामले को पहले ही बंद कर दिया था, जो आरोप विशेष रूप से नहीं हैं, हम OA और Misc ऐप्लकैशन का निपटान एक दिशा के साथ करते हैं कि प्रतिवादी-अधिकारियों को सतर्कता मैनुअल के पैरा 1.8 के प्रावधान के प्रकाश में और इस आदेश के पहले भाग में की टिप्पणियों के प्रकाश में आवेदन पर पुनर्विचार करें। जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आवेदक के खिलाफ ज्ञापन अनुलग्नक A-1 के बल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

OA और MA स्टैंड को उपरोक्त शब्दों में निपटाया गया है लेकिन मामले के तथ्य और परिस्थितियां के आधार पर, लागत का कोई आदेश नहीं होगा।"

(6) हमारी राय में, पूर्वोक्त दिशाएँ पूरी तरह से हैं सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के साथ सहमति रखती है। पूर्वोक्त मैनुअल का अध्याय III प्रारंभिक जांच / जांच से संबंधित है। अध्याय की धारा 1 पूछताछ करने के लिए एजेंसी से संबंधित है। पैरा 1.1 प्रदान करता है कि जैसे ही कोई निर्णय लिया गया है एक शिकायत में निहित आरोपों की जांच होगी, तो यह तय करना आवश्यक है कि क्या आरोपों की जांच विभागीय या पुलिस जांच होगी। पैरा 1.8. में, मैं स्पष्ट रूप से प्रदान करता हूं कि एक बार एक मामले को सीबीआई जांच के लिए संदर्भित किया गया है, आगे की जांच को उनपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक समानांतर जांच/ विभाग, संगठन से बचना चाहिए. विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही, सीबीआई द्वारा जांच के पूरा होने और रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए निर्देश सतर्कता मैनुअल के पूर्वोक्त धाराओं के अनुरूप है। पूर्वोक्त मैनुअल का अध्याय III की धारा 2 विभागीय एजेंसियां द्वारा प्रारंभिक जांच से संबंधित है. पैरा 2.1 प्रदान करता है: -

"2.1 विभागीय जांच के तय होने के बाद, सतर्कता अधिकारी को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए कि निर्धारित करने के लिए क्या *प्रथम दृष्टया* उनमें कुछ पदार्थ है । "

(7) पैरा 2.2 सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रारंभिक संचालन की एक विधि से संबंधित है। पैरा 2.3 विभाग के भीतर कार्यवाही के लिए केवल एक और कदम है। इसका सीबीआई द्वारा आयोजित जांच से कोई संदर्भ नहीं है। उपरोक्त मैनुअल अध्याय ।।। की धारा 3 सीबीआई द्वारा जांच से संबंधित है। पैरा 3.1 यह प्रदान करता है कि जब तक इसके विपरीत कोई विशेष कारण न हों, जिन मामलों की केंद्रीय ब्यूरो द्वारा जांच की जानी है,उन्हें जल्द से जल्द जांच सौंप दी जानी चाहिए। ऐसा करना विशेष रूप से जरूरी है ताकि संदिग्ध लोक सेवक द्वारा उसके खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट करने की संभावना के खिलाफ सुरक्षा की जाए। पूर्वोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई के माध्यम से और विभागीय से की जाने वाली जांच में एक स्पष्ट परिसीमन है। प्रारंभिक चरण में ही जांच के एक या दूसरे मोड के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। वर्तमान मामले में, मामला सीबीआई को सौंपा गया है, मामले को फिर से विभागीय रूप से खोलने का कोई औचित्य नहीं था। हमारी राय में, ट्रिब्यूनल ने कौशल को जारी किए गए शो-कारण नोटिस को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हम यह भी स्वीकार नहीं करते हैं कि पूर्वोक्त मैनुअल में निहित निर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। हमारी राय यह है कि ट्रिब्यूनल ने पैरा 1.8 को देखते हुए सही ढंग से आयोजित किया है कि विभाग शो-कारण नोटिस जारी नहीं कर सकता था। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के मामले **वीरेंद्र एस. हूडा और अन्य** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य (2). के** फैसले पर सही भरोसा किया है। पूर्वोक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि: –

> "4. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि प्रशासनिक अपीलकर्ता द्वारा निर्देश लागू नहीं किए जा सकते हैं और भर्ती की रिक्तियां उपलब्ध होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया को देखना एक संकीर्ण और गलत दृष्टिकोण होगा। जब राज्य द्वारा कोई नीति घोषित पद को भरने के तरीके के बारे में हो और वह नीति नियमों के संदर्भ में घोषित की गई है और लोक सेवा आयोग को निर्देश समय-समय जारी किए गए, तब तक माने जाएंगे, जब तक वह नियमों के निर्देश के विपरीत नहीं हैं।"

(2) जे.टी. 1999 (5) एस.सी. 621

(8) प्रशासनिक आदेश किसी भी अधिकार को प्रदान नहीं कर सकते हैं या कोई कर्तव्य नहीं लगा सकते, पर बहस करना अब संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के इस मामले का निपटान **भारत का संघ** *बनाम* **के.पी. जोसेफ और अन्य (3) में** किया गया था। **पैरा** 10 में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है: –

"10. **भारत का संघ** *बनाम* **एम / एस इंडो-अफगान एजेंसियां लिमिटेड. (1968) 2 एससीआर 366 पर पी. 377 में** इस न्यायालय ने आयात व्यापार नीति की प्रकृति पर विचार किया और कहा: –

"यह देखते हुए कि यह कार्यकारी चरित्र में है, इस न्यायालय ने माना है कि न्यायालयों में शक्ति है कि वह उपयुक्त मामलों में योजनाओ द्वारा लगाए गए दायित्वों के प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों को मजबूर कर सकते है।"

यह कहना कि एक प्रशासनिक आदेश कभी भी कोई अधिकार नहीं दे सकता है बहुत व्यापक प्रस्ताव होगा। ऐसे प्रशासनिक आदेश हैं जो अधिकारों को प्रदान करते हैं और कर्तव्यों को लागू करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि एक प्रशासनिक आदेश अधिकारों को निरस्त या दूर कर सकता है और हमने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत *ऑडी परिवर्तन* को इस क्षेत्र में आयात किया है। एक बहुत बोधगम्य लेखक ने लिखा है: –

"हम श्री हैरिसन के उदाहरणों में से एक का विनियमन लेते हैं, ब्रिटिश युद्ध अधिकारी से कि कोई भर्ती नहीं होगी सूचीबद्ध जो पांच फीट छह इंच ऊंचा नहीं है. मान लीजिए एक भर्ती अधिकारी एक आदमी है जो पाँच फीट है केवल ऊंचाई में पांच इंच, और उसे राजा का भुगतान करता है शिलिंग: बाद में अधिकारी द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है उनके खातों में कम होने के लिए सरकार; के बीच अन्य वस्तुओं का दावा है कि उन्हें अंडरस्क्राइब्ड भर्ती के लिए भुगतान की जाने वाली शिलिंग की अनुमति दी गई है. न्यायालय को विचार करना होगा और इस विनियमन की आपूर्ति और, जो भी इसका प्रभाव है हो सकता है, यह प्रभाव न्यायालय द्वारा दिया जाएगा ठीक उसी तरह जैसे कि एक क़ानून प्रदान करने के लिए दिया जाएगा उस हत्यारे को फांसी दी जाएगी, या वह अंतिम वसीयत करेगा दो गवाह हैं।" (जॉन चिपमैन ग्रे पर "द प्रकृति और कानून के स्रोत ")"

(3) 1973 (1) S.L.R. 910

(9) पूर्वोक्त टिप्पणियों में संदेह का कोई तरीका नहीं है विभाग सतर्कता नियमावली में निहित निर्देशों से बाध्य है, जब तक कि वे किसी भी बेहतर कानून के विरोधाभासी नहीं हैं, जैसे कि प्रोविसो के तहत तैयार विभागीय नियम अनुच्छेद 309 के तहत भारत का संविधान, विधानमंडल और द्वारा प्रख्यापित क़ानून संविधान के प्रावधान. कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है यह दिखाने के लिए कि उपरोक्त के पैरा 1.8 में निहित निर्देश मैनुअल किसी भी वैधानिक प्रावधानों या विभागीय के विपरीत हैं नियम. वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की दलील केवल यह है कि उनके पास है पैरा के आधार पर एक समानांतर जांच करने की शक्ति 3.18 का पूर्वोक्त मैनुअल. मैनुअल के पैरा 3.18 के तहत प्रदान करता है: –

"3.18 अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई कानूनी पट्टी नहीं है अपराधी लोक सेवक के लिए लागू नियमों के तहत जहां आपराधिक मुकदमा पहले से ही लंबित है, और आम तौर पर परिणाम की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को प्रभावित करने वाले, क्योंकि के अवयव आपराधिक अभियोगों में कदाचार / अपराध और विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ प्रमाण की मात्रा दोनों मामलों में आवश्यक समान नहीं हैं. आपराधिक मामलों में, सजा के लिए आवश्यक प्रमाण से परे होना चाहिए उचित संदेह, जबकि विभागीय कार्यवाही में संभाव्यता के प्रसार पर आधारित प्रमाण पर्याप्त है आरोपों को रखने के लिए साबित किया गया है. हालाँकि, बाद की कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित कर सकता है विरोधाभास हो सकता है जो गवाह बना सकते हैं उक्त कार्यवाही में उनके जमा में. यह होगा, इसलिए, आवश्यक है कि सभी प्रासंगिक मामले हों निर्णय लेते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विचार किया जाता है एक साथ विभागीय शुरू करने या न करने पर कार्रवाई."

(10) हमारी राय में, पूर्वोक्त प्रावधान का कोई आवेदन नहीं है वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए. यह प्रदान करता है कि कोई कानूनी नहीं है लागू नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बार लोक सेवक जहां आपराधिक मुकदमा पहले से ही लंबित है. में वर्तमान मामला, किसी भी आपराधिक कार्यवाही का कोई सवाल ही नहीं है कौशाल के खिलाफ लंबित है. केवल एक प्रारंभिक जांच की जा रही है सी.बी.आई. द्वारा संचालित. आपराधिक कार्यवाही लंबित बताई जाती है जब कोई आरोप आपराधिक अदालत द्वारा लगाया जाता है. पूर्वोक्त अवस्था

जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट आती है न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया कि क्या है पर्याप्त सामग्री *प्रथम दृष्टया* आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए. अन्यथा भी, पैरा 3.18 के संबंध में प्रस्तुत करने को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा इस मामले को O.A में नहीं उठाया गया था. यह बिंदु पहली बार उठाया गया था जब समीक्षा आवेदन का तर्क दिया गया था. यह समीक्षा आवेदन में भी नहीं किया गया था. हमारे विचार में ट्रिब्यूनल ने पैरा 3.18 के संबंध में प्रस्तुतियाँ को सही ठहराया है. हालाँकि, श्री एस.पी. जैन, सीनियर सीखा. वकील ने माना कि समीक्षा आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से भरोसा किया है 1 नवंबर, 1996 के एक पत्र पर जो एक द्वारा लिखा गया था पी.के. मथुर, प्रबंध (सतर्कता), कौशाल को जिसमें यह था निम्नानुसार उल्लेख किया गया है: –

"कृपया अपने D..0 का संदर्भ लें. पत्र सं. PAJSRM7Misc./96, दिनांक 1 नवंबर, 1996 को कार्यकारी निदेशक को संबोधित किया (सतर्कता), FCI, Hqrs।, विभिन्न परिणामों के बारे में के आधार पर आपके खिलाफ जांच शुरू की गई अनाम / छद्म शिकायतें, प्रेस रिपोर्ट, कुछ यूनियनों से या जोनल ऑफिस से प्राप्त अभ्यावेदन (उत्तर).

उपरोक्त के संबंध में, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि Hqrs में प्राप्त संदर्भ से संबंधित जांच. ध्वनि चावल और इसकी बिक्री के उन्नयन के संबंध में उप-मानक चावल के रूप में, लकड़ी के बक्से की खरीद, पोस्टिंग और AH (Ocs ') के हस्तांतरण और लकड़ी के बाफलों की खरीद, 1994-95 में एफसीआई धान की गैर-इच्छुक की गलतफहमी, आदि तब से सक्षम के आदेशों के साथ बंद कर दिए गए हैं अधिकार. इन मामलों के संबंध में प्रासंगिक फाइलें जिसे Hqrs के सतर्कता प्रभाग द्वारा जब्त किया गया था। जा रहे हैं आर.ओ. कूरियर के माध्यम से.

अब तक आंदोलन में अनियमितताओं से संबंधित फाइलें पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों से जे एंड के लिए खाद्य पदार्थों की मार्च से जून, 1995 की अवधि के दौरान घाटी हैं संबंधित, अभी भी उसी के संबंध में आवश्यक हैं श्री पी के खिलाफ शिकायत. राम, पूर्व ZM (N). के बाद से मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक रिकॉर्ड की आवश्यकता हो सकती है (CVC) आदि) उसी को फिलहाल नहीं बख्शा जा सकता."

(11) पूर्वोक्त पत्र के आधार पर, ट्रिब्यूनल के पास था निर्णय के पैराग्राफ 20 में कुछ अवलोकन किए. यह है किया गया *अन्य बातों के साथ,* ट्रिब्यूनल द्वारा देखा गया कि सक्षम प्राधिकरण ने जांच के बाद मामले को पहले ही बंद कर दिया था, जो आरोपों को विशेष रूप से नकारा नहीं गया है. हम विचार के हैं राय है कि ट्रिब्यूनल की पूर्वोक्त टिप्पणियों को देखा गया है पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर ले लिया. में निहित प्रावधानों के मद्देनजर सतर्कता मैनुअल के पैरा 1.8, विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई द्वारा जांच पूरी होने पर लिया जाना चाहिए C.B.I., उनकी रिपोर्ट के आधार पर. पैरा 3.11 (i) (ii) के तहत पूर्वोक्त मैनुअल, सी.बी.आई. सिफारिश करने की शक्ति है विभागीय कार्रवाई की जा सकती है जहां आरोप गंभीर हैं प्रकृति, लेकिन उपलब्ध सबूत आपराधिक लॉन्च करने के लिए पर्याप्त नहीं है अभियोजन. यदि विभागीय जांच शुरू की जाती है सीबीआई की रिपोर्ट के पूरा होने पर, केवल उस स्तर पर, पूर्वोक्त पत्र के साक्ष्य मूल्य को देखना होगा. केवल इसलिए कि पूर्वोक्त पत्र को ध्यान में रखा गया है ट्रिब्यूनल द्वारा अपने निर्णय को अधिकार क्षेत्र के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा या मनमाना भी. पारस 3.10, 3.11 में निहित प्रावधान, 3.11 (i) और (ii) के तहत हैं: -

"3.10 यदि जांच पूरी होने पर, सी.बी.आई निष्कर्ष है कि suficient सबूत के लिए आगे आ रहा है एक आपराधिक मुकदमा शुरू करना, फिर अंतिम रिपोर्ट ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय को भेज दी जाएगी यदि अभियोजन को मंजूरी की आवश्यकता है तो सतर्कता आयोग राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए जाने वाले किसी भी कानून के तहत. यदि अन्य मामले हैं, तो रिपोर्ट प्राधिकरण को भेज दी जाएगी अभियोजन को मंजूरी देने के लिए सक्षम. रिपोर्ट होगी निर्धारित में मसौदा मंजूरी आदेश के साथ फार्म *(देख* अध्याय VII), और रैंक देगा और खारिज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पदनाम सेवा और कानून या नियमों के तहत अपराधी अधिकारी जो ऐसा करने के लिए सक्षम है. आगे की कार्रवाई ऐसी रिपोर्टों पर लिया जाना अध्याय VII में वर्णित है.

3.11 अन्य मामलों में जिनमें उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए, सी.बी.आई. करने के लिए आ सकता है निष्कर्ष यह है कि :

(i) आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं नियमित विभागीय कार्रवाई को उचित ठहराया जा रहा है संबंधित लोक सेवक के खिलाफ. अंतिम रिपोर्ट

ऐसे मामलों में (ए) मसौदा लेखों के साथ होगा
निर्धारित प्रपत्र में तैयार प्रभार *(देख* अध्याय
एक्स), (बी) प्रत्येक के समर्थन में आवेगों का एक बयान शुल्क, और (ग) दस्तावेजों और गवाहों की सूची पर भरोसा किया आरोपों और आरोपों को साबित करने के लिए; या

(ii) जबकि औचित्य के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है अभियोजन या नियमित विभागीय कार्रवाई, वहाँ है ईमानदारी या अखंडता के बारे में एक उचित संदेह संबंधित सरकारी सेवक, अंतिम रिपोर्ट ऐसे मामलों में नोटिस लाने की कोशिश करेंगे अनुशासनात्मक अधिकार अनियमितता की प्रकृति या इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई के लिए लापरवाही हो सकती है संभव या उचित माना जाता है। ”

(12) पूर्वोक्त प्रावधान इसे बहुतायत से स्पष्ट करते हैं विभागीय कार्यवाही को केवल प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि शो-कारण नोटिस जारी किया गया है सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच की पेंडेंसी के दौरान. श्री एस.पी. जैन, सीनियर सीखा. वकील ने कई निर्णयों का हवाला दिया है प्रस्ताव के समर्थन में कि विभागीय कार्यवाही हो सकती है किसी कर्मचारी को अपराधी द्वारा बरी किए जाने के बाद भी जारी रखा गया कोर्ट. पूर्वोक्त प्रस्ताव कानून में अच्छी तरह से स्थापित है. में वर्तमान मामला, इस स्तर पर, न तो कोई अभियोजन है और न ही ए आपराधिक कार्यवाही में कौशाल का बरी होना. इसलिए सीखे गए सीनियर द्वारा उद्धृत निर्णय. इस स्तर पर वकील, प्रासंगिक नहीं है. के मामले में **कर्नाटक राज्य** *बनाम* **टी। वेंकटारामनप्पा (4),** यह माना गया था कि मानक एक आपराधिक अभियोजन में आवश्यक सबूत से अलग है विभागीय कार्यवाही में आवश्यक मानक. के मामले में **भारत कुकिंग कोल लि.** *बनाम* **बिभूति कुमार सिंह और अन्य, (5)** कर्मचारी को सीबीआई द्वारा छुट्टी दे दी गई थी पर्याप्त सबूतों की अनुपलब्धता का आधार. विभागीय जांच को प्रमाण के सख्त मानक के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी जैसा कि आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक नहीं है विभागीय कार्यवाही. के मामले में **राजस्थान राज्य** *बनाम* **श्री बी.के. मीना और अन्य, (6)** फिर से यह आयोजित किया गया है

---

(4) 1997 (1) एस.सी.टी. 484

(5) 1995 (1) एस.सी.टी. 20

(6) जे.टी. 1996 (8) एस.सी. 684

आपराधिक मुकदमा चलाने और दोनों के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है एक साथ जाने के लिए विभागीय कार्यवाही. यह भी रहा है देखा गया कि यह 'अपमानजनक', 'सलाह' या 'उपयुक्त' नहीं हो सकता है' आपराधिक मामले होने पर अनुशासनात्मक जांच के साथ आगे बढ़ना समान शुल्क पर लंबित. यह भी देखा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही का रहना निर्धारित किया जाना है किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में और उस ओर से कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं बनाए जा सकते. में का मामला **नेल्सन मोटिस** *बनाम* **भारत संघ और एक अन्य, (7)** सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि प्रकृति और गुंजाइश एक आपराधिक मामला विभागीय लोगों से बहुत अलग है कार्यवाही और बरी करने का आदेश समाप्त नहीं हो सकता विभागीय कार्यवाही. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि ट्रिब्यूनल ने बताया था कि जिन कृत्यों के कारण दीक्षा हुई थी विभागीय कार्यवाही बिल्कुल वही थी जो थीं आपराधिक कार्यवाही का विषय. के मामले में **Jaipal** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य,** इस की एक डिवीजन बेंच न्यायालय ने माना है कि साबित करने के लिए अभियोजन के प्रमाण का मानक एक आपराधिक मुकदमे में आवश्यक अपराध उचित संदेह से परे है. विभागीय कार्यवाही में, देयता पर बाहर किया जा सकता है संभावनाओं का प्रसार. इसलिए, .a अनुशासनात्मक जांच एक आपराधिक मुकदमे की पीठ पर नहीं रखा जाना चाहिए. इसलिए, विभागीय कार्यवाही अपराधी के साथ जारी रह सकती है परीक्षण. के मामले में **देश बंधु पल्लन** *बनाम* **ओरिएंटल बैंक वाणिज्य के, (8)** इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के पास है कानून को दोहराया कि केवल एक आपराधिक आरोप में बरी हो गया एक ही आरोप एक अपराधी को भगाने के लिए पर्याप्त नहीं है विभागीय कार्यवाही में एक ही प्रभार से कर्मचारी कुंआ.

(१३) जैसा कि ऊपर दिया गया है, हम इस विचार के हैं श्री द्वारा उद्धृत पूर्वोक्त मामलों से उभरने वाले कानून के प्रस्ताव. एस.पी. जैन, सीनियर सीखा. वकील तथ्यों में लागू नहीं होते हैं और वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ. वर्तमान में न तो कोई अपराधी है पूर्ण परीक्षण के बाद अभियोजन और न ही बरी. हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा इन प्राधिकरणों पर निर्भरता पूरी तरह से थी गलत समझा. हालाँकि, जब से सीनियर ने सीखा है. के लिए पेश होने वाले वकील

(7) जे.टी. 1992 (5) एस.सी. 511
(8) 2002 (2) एस.सी.टी. 551

याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा था कि प्रत्येक प्राधिकरण उसके द्वारा उद्धृत किया गया है इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए, हमने पूर्वोक्त निर्णयों का संदर्भ देना अपना कर्तव्य महसूस किया.

(१४) श्री जैन, सीनियर सीखे. वकील ने एक संख्या का भी हवाला दिया है ट्रिब्यूनल ने जिन सबमिशन के समर्थन में अधिकारियों को मिटा दिया मनोरंजन में कानून में ओ.ए. कौशाल द्वारा दायर की गई. के अनुसार सीनियर सीखा. वकील, न्यायालय द्वारा इसे रद्द करने की अनुमति नहीं है प्रारंभिक चरण में विभागीय कार्यवाही. के मामले में **विशेष निदेशक और अन्य** *बनाम* **मोहम्मद. गुलाम गोदाम और दूसरा, (9),** सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पर विचार किया *स्थिति* बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा दी गई. उस मामले में, प्रतिवादी नहीं. मैं लगभग रु। से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार था. 270 करोड़. आगे आरोप थे कि दस्तावेज हैं जाली और खातों में हेरफेर किया गया है. यह भी मामला था अपीलकर्ता कि किसी भी घटना में, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए स्वतंत्र था उन सभी बिंदुओं को रद्द कर सकता है जो पहले रिट याचिका में लिए गए थे नोटिस जारी करने वाला प्राधिकरण. ऐसा करने के बजाय, वह भाग गया उच्च न्यायालय. उच्च न्यायालय ने न केवल रिट याचिका का मनोरंजन किया, बल्कि अंतरिम राहत भी दी, जो वास्तव में अनुमति देने के लिए थी योग्यता पर सुनवाई से पहले ही रिट याचिका. यह आरोप लगाया गया था विदेशी मुद्रा के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा). इन परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय निम्नानुसार देखा गया: –

> "बड़ी संख्या में मामलों में इस न्यायालय ने पदावनत किया है शो की वैधता पर सवाल उठाने वाले उच्च न्यायालयों के मनोरंजक रिट याचिकाओं का अभ्यास नोटिस को रोक देता है जांच के रूप में प्रस्तावित और सेवानिवृत्त होने की पूछताछ भागीदारी और के साथ वास्तविक तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया पार्टियों की उपस्थिति. <u>जब तक, उच्च न्यायालय नहीं है संतुष्ट हैं कि शो-कारण नोटिस पूरी तरह से गैर था *est* के पूर्ण इच्छा के लिए कानून की नजर में के यहां तक कि तथ्यों, रिट याचिकाओं की जांच करने का अधिकार केवल पूछने और एक के लिए मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए दिनचर्या और रिट याचिकाकर्ता की बात होनी चाहिए</u>

हमेशा शो-कारण का जवाब देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए नोटिस और रिट याचिका में हाइलाइट किए गए सभी स्टैंड लें. (जोर दिया गया). क्या किसी कानूनी परिसर में शो-कारण नोटिस की स्थापना की गई थी, यह एक अधिकार क्षेत्र है मुद्दा जो नोटिस के प्राप्तकर्ता द्वारा भी आग्रह किया जा सकता है और इस तरह के मुद्दों को भी स्थगित किया जा सकता है शुरू में बहुत नोटिस जारी करने वाला प्राधिकरण, पहले के दुखी होकर कोर्ट का रुख कर सकते थे. इसके अलावा, जब न्यायालय एक अंतरिम आदेश पारित करता है, इसे सावधान रहना चाहिए देखें कि वैधानिक पदाधिकारियों विशेष रूप से और विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित की गई निंदा नहीं की जाती है शक्तियों और प्राधिकरण को शुरू में मामला तय करना और यह सुनिश्चित करें कि अंतिम राहत जो हो सकती है या नहीं अंत में रिट याचिका में दी गई है अंतरिम द्वारा दहलीज पर भी याचिकाकर्ता सुरक्षा दी गई। "."

(15) पूर्वोक्त के बल पर दिए गए भागों का एक अनुमान अर्क दिखाएगा कि ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र होगा मनोरंजन के लिए ओ.ए. जहां शो-कारण नोटिस को धैर्यपूर्वक दिखाया गया है, अधिकार क्षेत्र के बिना. निर्णय के पहले भाग में, हम पहले ही यह मान चुके हैं कि कुल मिलाकर कौशाल को शो-कारण नोटिस जारी किया गया था सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन. यह अलग है, ट्रिब्यूनल ने कौशाल को अंतिम राहत नहीं दी है. द विभाग के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता होगी कौशाल के मामले में यह पाया जाता है कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं हैं के समापन पर किसी भी आपराधिक अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाना सी.बी.आई. द्वारा जांच.

(16) के मामले में **कार्यकारी इंजीनियर, बिहार राज्य आवास बोर्ड** *बनाम* **रमेश कुमार सिंह और अन्य, (10)** अपीलकर्ता ने 1 प्रतिवादी को एक शो-कारण नोटिस जारी किया था दिखाने के लिए कारण के रूप में क्यों घर से बेदखल करने का आदेश सवाल उसके खिलाफ पारित नहीं किया गया क्योंकि वह अवैध रूप से था और अनधिकृत रूप से उसी में रह रहे हैं. जवाब देने के बजाय शो-कारण नोटिस, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की. द उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुना और यह विचार किया कि 1 प्रतिवादी

(10) जे.टी. 1995 (8) एस.सी. 331

बोर्ड का किरायेदार नहीं है और इसलिए बोर्ड का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा अपनी गति से या उदाहरण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए 4 वें प्रतिवादी जो संबंधित तिमाही के अलॉट्टी थे. यह उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था कि एलोटे की तलाश हो सकती है बिहार इमारतों के नीचे एक सूट लाकर उचित उपाय (लीज, रेंट एंड एविक्शन) कंट्रोल एक्ट। परिणाम में, बेदखली कार्यवाही रद्द कर दी गई. ऐसी परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विवाद में मूल या मौलिक तथ्य जैसा है 1 प्रतिवादी के बीच तिमाही का मालिक कौन था और 4 प्रतिवादी. वास्तव में, एलोटे ने बोर्ड से शिकायत की थी पहली प्रतिवादी ने जबरन तिमाही में प्रवेश किया था. के बाद से परिसर बोर्ड से संबंधित है, यह आरंभ करने के लिए सक्षम था अधिनियम के तहत कार्यवाही। यह ऐसी परिस्थितियों में था कि सुप्रीम कोर्ट के तहत मनाया गया: –

> "10., हम इस मामले में चिंतित हैं, के मनोरंजन के साथ एक सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शो कारण नोटिस के खिलाफ याचिका. इसे ध्यान में रखना चाहिए वैधानिक के खिलाफ कोई हमला नहीं है/ मामले को नियंत्रित करने वाले प्रावधान. का कोई सवाल नहीं किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन संविधान कथित या सिद्ध है. ऐसा नहीं कहा जा सकता Ext. पी -4 नोटिस है *पूर्व facie* एक "अशक्तता" या पूरी तरह से "बिना क्षेत्राधिकार "उस अभिव्यक्ति के पारंपरिक अर्थ में -यह कहना है कि यहां तक कि शुरुआत या दीक्षा कार्यवाही, उसके चेहरे पर और बिना किसी चीज के अधिक, पूरी तरह से अनधिकृत है. ऐसे मामले में, के लिए के अनुच्छेद 226 के तहत एक लिखित याचिका का मनोरंजन एक शो-कारण नोटिस के खिलाफ भारत का संविधान, उस पर चरण, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्राधिकरण के पास कोई शक्ति नहीं है या क्षेत्राधिकार, प्रश्न में जांच पर प्रवेश करने के लिए. में अन्य सभी मामले, यह केवल उचित है कि पार्टी को चाहिए वैकल्पिक उपाय का लाभ और कारण के खिलाफ प्रदर्शन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष और ले लो क्षेत्राधिकार के बारे में भी आपत्ति. की स्थिति में एक प्रतिकूल निर्णय, यह निश्चित रूप से उसके लिए खुला होगा मामले के रूप में अपील या संशोधन में या तो हमला करें हो सकता है। या उचित मामलों में, क्षेत्राधिकार का आह्वान करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत."

(17) हमारी राय में, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ट्रिब्यूनल द्वारा मनोरंजन में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करना होगा इस आधार पर OA कि शो-कारण नोटिस नहीं हो सकता था सतर्कता मैनुअल के पैरा 1.8 के मद्देनजर जारी किया गया.

(18) के मामले में **भारत संघ और एक अन्य** *बनाम* **अशोक काकर, (11).** इस मामले में, ट्रिब्यूनल ने मनोरंजन किया था OA और वास्तव में केवल आधार पर चार्ज-शीट को रद्द कर दिया आवेदक को प्रस्तुत करना कि मामला पहले था विभाग द्वारा जांच की गई और बंद कर दिया गया. इसलिए, यह आयोजित किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कर्मचारी के पास पूरा अवसर होगा चार्ज-शीट के उत्तर और उपलब्ध बाकी बिंदुओं पर उसे. वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने कोई भी समझौता नहीं किया है चार्ज शीट. प्रारंभिक जांच सीबीआई के पास लंबित है. एक समानांतर प्रारंभिक जांच द्वारा संचालित करने की मांग की जाती है वह विभाग जो अनुच्छेद 1.8 के तहत स्वीकार्य नहीं है सतर्कता मैनुअल. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अवलोकन 1 नवंबर, 1996 के पत्र के संबंध में पैरा 20 में ट्रिब्यूनल (अनुलग्नक पी -7) को अंतिम नहीं माना जा सकता है सबूत पर राय·पूर्वोक्त पत्र का ry मान जो होगा विभागीय मामले में उचित स्तर पर देखा जाना चाहिए के पूरा होने पर कुशाल के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है सीबीआई की जांच. के मामले में **भारत संघ और अन्य** *बनाम* **ए.एन. सक्सेना (12),** सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि ट्रिब्यूनल को रहने देने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए था एक अंतःविषय चरण में एक अनुशासनात्मक कार्यवाही. ये टिप्पणियों वह तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा मेमोरेंडम जारी करने के रूप में वर्तमान मामले में जो है ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिया गया था, स्पष्ट रूप से प्रासंगिक के विपरीत था सतर्कता मैनुअल के प्रावधान.

(19) इस मामले की उत्सुकता से जाँच करने के बाद, हम इसके हैं माना जाता है कि रिट याचिका किसी भी तरह से पूरी तरह से रहित है योग्यता. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है. नहीं लागत.

(11) 1995 (7) एस.एल.आर. 430
(12) 1992 (4) एस.एल.आर. 1 1

R.N.R.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा